



जनसंख्या बढ़ी, प्रजनन दर घटी

राजेश कुमार। नई दिल्ली

भारत की जनसंख्या 2025 में एक अरब 46 करोड़ (1.46 बिलियन) तक पहुंचने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसंख्याकी रिपोर्ट के अनुसार जो यह भी बताती है कि देश का कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिशत प्रजनन स्तर से नीचे 1.9 तक गिर गई है, जो एक महत्वपूर्ण जनसंख्याकीय बदलाव का सकेत है।

भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वर्तमान में प्रति महिला 2.0 बच्चे हैं। इकाई मतलब है कि औसत भारत में एक महिला से उसके प्रति जन वर्षों (आमतौर पर 15-49 वर्ष की आयु) के दौसून 2 बच्चे होने की उम्मीद की जाती है।

2021 के लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की स्थिरों के अनुसार, यह दर 2020 के खिलाफ बढ़ी हुई है। इकाई मतलब है कि औसत भारत में एक महिला से उसके प्रति जन वर्षों (आमतौर पर 15-49 वर्ष की आयु) के दौसून 2 बच्चे होने की उम्मीद की जाती है।

2025 स्टेट अफ वर्ल्ड पॉल्यूशन (एसओडब्ल्यूपी) रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि वास्तविक संकट जनसंख्या के आकार में नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के स्वतंत्र और जिम्मेदारी से यह तब करने के अधिकाका समर्थन करता है, जबकि 20 प्रतिशत को अधिक या कम बच्चे पैदा करने की अधिकारी बच्चा का अनुभव होता है। उद्देश्यीय रूप से, 23 प्रतिशत ने दोनों का सामना किया।

उल्लेखीय रूप से, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, तब औसत महिला के लगभग छह बच्चों की छाती पर अनुसार, तीन में से एक बच्चा भारतीय (36 प्रतिशत) अनुसंधान पर्याधारण का कार्रवाई करता है, जबकि 20 प्रतिशत को अधिक या कम बच्चे पैदा करने की अधिकारी बच्चा का अनुभव होता है। उद्देश्यीय रूप से, 23 प्रतिशत ने दोनों का सामना किया।

उल्लेखीय रूप से, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, तब औसत महिला के लगभग छह बच्चों की छाती पर अनुसार, तीन में से एक बच्चा भारतीय (36 प्रतिशत) अनुसंधान पर्याधारण का कार्रवाई करता है, जबकि 20 प्रतिशत को अधिक या कम बच्चे पैदा करने की अधिकारी बच्चा का अनुभव होता है। उद्देश्यीय रूप से, 23 प्रतिशत ने दोनों का सामना किया।



प्रतीकालक दिन

हैं। यह मोल का पथर स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति को दर्शाता है, लेकिन कुल प्रजनन दर में क्षेत्रीय विविधता का छुपाता है, जो कि एक महिला के जीवनकाल में होने वाले बच्चों की अनुसंधान।

2025 स्टेट अफ वर्ल्ड पॉल्यूशन (एसओडब्ल्यूपी) रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि वास्तविक संकट जनसंख्या के आकार में नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के स्वतंत्र और जिम्मेदारी से यह तब करने के अधिकाका समर्थन करता है, जबकि 20 प्रतिशत को अधिक या कम बच्चे पैदा करने की अधिकारी बच्चा का अनुभव होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आवादी बाता देश है, जिसमें लगभग एक अरब 50 करोड़ (1.5 बिलियन) लोग हैं, यह संख्या लगभग 40 साल बाता देश है, जिसमें लगभग एक अरब 70 करोड़ (1.7 बिलियन) तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आंकड़ों के पीछे लाखों जोड़ों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपने विवरों को शुरू करने या बढ़ाने का फैसला किया, साथ ही उन महिलाओं की कहानियां भी हैं जिन्होंने यह साथ करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी बोला है। यह अनुभव अपने विवरों को शुरू करने या बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें लगभग एक अरब 70 करोड़ (1.7 बिलियन) तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आंकड़ों के पीछे लाखों जोड़ों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपने विवरों को शुरू करने या बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें 0-14 आयु वर्षों में 24 प्रतिशत, 10-19 में 17 प्रतिशत और 10-24 में 26 प्रतिशत है। देश की 68 प्रतिशत आवादी कार्ययोग्य आयु (15-64) की है, जो पर्याप्त रोजगार और नीति समर्थन के साथ सभावित जनसांख्यिकीय लगभग अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का प्रदान करती है। बुजुर्ग आवादी वर्तमान में सात प्रतिशत है, एक आंकड़ा जो

अनेक दशकों में जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ बढ़ने की उम्मीद है। 2025 तक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में,

मनमानी स्कूल फीस बढ़ाने पर अध्यादेश को मंजूरी

राजेश कुमार। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अग्रवाई में दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस से फैसले बढ़ाने पर मचे बावल और विवेद के बाद, स्कूलों द्वारा लोगों जो जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में,

राष्ट्रीय-10 गोमांस को हिंदुओं के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा: हिमंत

राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली की गुरुकांडी रेखा गुप्ता के अग्रवाई में दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस से फैसले बढ़ाने पर मचे बावल और विवेद के बाद, स्कूलों द्वारा लोगों जो जीवन व्यापार छाती हैं, जो अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में, जब भारत की जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ (436 मिलियन) थी, और महिला के लगभग छह बच्चों के लिए एक अधिकारी खोला जाने वाली फैसले को विनियमित करने और मंजूरी दें दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फैसले के निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता) लाने के लिए एक अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दें दी है।

मानवीय संकट थुनबर्ग का अभियान

ग्रेटा थुनबर्ग गाजा में मानवीय संकट के प्रति दुनिया को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। ऐसे समय जब मौन रहने का आर्थ संलिप्त हो सकती है, ग्रेटा थुनबर्ग एक बार फिर दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने जा रही है। इस बार जलवायु के बजाय मानवीय संकट उके अभियान के केन्द्र में है। उनका नवीनतम कृत्य गाजा में इसाइली नौसेना द्वारा आरोपित नाकेबंदी तकाल तोड़ना है ताकि धूम, धूख और निराशा के शिकार क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। थुनबर्ग और 11 अन्य एकटरिनों के साथ पालों से चलने वाले छोटे से जहाज मैडलिन से सिस्टीन से अपनी यात्रा शुरू की और उपका लक्ष्य न केवल सहायता देना, बल्कि उस पौँड का गवाह बनना है जो गाजा में आम हो गई है। गाजा पौँड में दो मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं जो इसाइली थलसेना, बायुसेना और नौसेना द्वारा 2007 से नाकेबंदी का शिकार है। हमास पर लगाने के प्रयासों ने पिछोने सालों में व्यवस्था का रूप ले लिया है। इसमें सिस्टीनों की सीमित आवागमन, आर्थिक डरहाव तथा लगातार बमबारी से निशान बनाया जा रहा है।

इसाइल और हमास के बीच जारी वर्तमान टकराव ने बार-बार गाजा की ढांचात संचार का खंडर में बदला है, उनके लोगों को आशात पहुंचाया है तथा भविष्य को अनिश्चित तक हो सकता है। एक अक्टूबर, 2023 को इसाइल पर हुए हमास के आंतरिक हमले के बाद इसाइल ने अपनी सेनिक आक्रमणकाता बढ़ा कर वहां लगाया तीन महीने से 'पूर्ण नाकेबंदी' की है। इस कालखंड में भोजन, ईंधन और दवाओं की सामर्थी लगभग पूरी तरह काट दी गई है। हालांकि, इसके बाद से थोड़ी बहुत सहायता पहुंची है, परं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपनी की आशंका जारी रखी है। सूधार कराये गए अन्य मानवतावादी समझों के अनुसार गाजा में बच्चे धूम, धूख का शिकार हैं, अस्पताल ध्वनि हो रहे हैं तथा जलवायु एवं बृक्षिकर्म के लिए विचायत ग्रेटा थुनबर्ग ने उसी स्थिति और ताकालिकता के साथ गाजा में मानवीय आपातस्थिति की ओर ध्यान दिया है। उनके साथी एकटरिनों में ब्राजील की सोशल एकटरिन शिथाया अविला और यूरोपीय संसद में फ्रांसीसी सदस्य रीमा हसन शामिल हैं। ग्रेटा नाकेबंदी तोड़ने के बाद महत्वपूर्ण सालाई पहुंचाना चाही है। उनकी यात्रा न केवल प्रतीकात्मक, बल्कि एक नैतिक खाली स्थान भरने का प्रयास है जहां दुनिया भर के राजनेता विफल हो गए हैं।

इसाइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 'मैडलीन' को गाजा पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने थुनबर्ग और उनके साथी एकटरिनों को विराधी और 'हामास प्रचारक' बताया है। लेकिन मानवतावादीयों को दुश्मन घोषित करने से गाजा में व्यापक भयानक स्थिति समाप्त नहीं होती है। इसका अर्थ केवल इसाइल द्वारा नाकेबंदी में मानवीय तत्वों का अभाव है। ग्रेटा थुनबर्ग के मिशन का राजनीति से सोरकार नहीं है, बल्कि यह केवल मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा है। जब सकारे पूरी जासूखा को मनुष्य समझने से इनकार कर दें तो सिविल सोसाइटी के विराधी होना पड़ता है। उनका पालों से चलने वाला जहाज बहाने और मानवीय गरिमा लेकर जा रहा है। यह सहायता से बहु का इस बात का प्रतीक है कि दुनिया देख रही है और इस समय चुप्पी कोर्ट विकल्प नहीं है। उनका समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि वे ऐसा काम कर रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करने में विफल रहे हैं। वे पीढ़ित जनसंख्या को असली सहायता और असली सद्व्यवहार देने के साथ ही उस पर ध्यान देने में विफल रही हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवीय सहायता कोई धमकी न हो कर एक अधिकार है। गाजा में एक पालों से चलने वाले जहाज से ग्रेटा थुनबर्ग की यात्रा केवल थोड़ी सी सालाई पहुंचाना चाही है। इसका अर्थ साझा मानवीयता पर जोर देना है। इसका अर्थ निश्चयता को 'न' कहना है। इसके साथ-साथ जैसे आंतकीं संगठनों का समूल अंत भी जरूरी है।

भारत की कुशल श्रमशक्ति

विकसित दुनिया को इस समय पूँजी के बजाय कुशल, गतिशील व उत्साही लोगों की आवश्यकता है। भारत अपनी युवा व कुशल श्रमशक्ति से यह जरूरत पूरी कर सकता है। इसके लिए व्यापक कौशल प्रशिक्षण जरूरी है।

दिवेश सूर्य
(लेखक, कौशल प्रशिक्षण से संबद्ध हैं)

वर्ष 2030 तक दुनिया को श्रमशक्ति की अभूतपूर्व कमी का शिकाया होना पड़ सकता है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ब्रिटेन और अस्ट्रेलिया जैसी विकासित अर्थव्यवस्थाओं में यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया' गति फाउंडेशन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह कमी 2050 तक 250 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसका कारण बुद्धार्थी है। इस प्रकार विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया'



विकासित दुनिया में व्यवस्था को बदलने वाले लोगों को आशात पहुंचाया है, तथा भविष्य को अनिश्चित तक हो सकता है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया' गति फाउंडेशन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह कमी 2050 तक 250 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसका कारण बुद्धार्थी है। इस प्रकार विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया'

दलाल लाने से दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। इस प्रकार विदेशों में रोजगार भारत में संकरीत होती है और धोरेल श्रमशक्ति है। हालांकि, स्वचालिकरण और कृत्रिम विकास अर्थव्यवस्थाओं में यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया'

विकासित दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। इस प्रकार विदेशों में रोजगार भारत में संकरीत होती है और धोरेल श्रमशक्ति है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया'

की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनौती विदेशों में ज्यादा कामगार भेजने की नहीं, बल्कि की वैशिक पहुंच में महत्वपूर्ण योगदान करेगा और सही उद्योगों में भेजने की नीतीक वार्ता का गठन करेगा। यह कमी 2030 तक मिलता है कि यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया'

की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनौती विदेशों में ज्यादा कामगार भेजने की नहीं, बल्कि की वैशिक पहुंच में महत्वपूर्ण योगदान करेगा और सही उद्योगों में भेजने की नीतीक वार्ता का गठन करेगा। यह कमी 2030 तक मिलता है कि यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'लोलीवाल असेंड टैलेट फार्म इंडिया'

विकास, डिजिटल सार्वजनिक कल्याण तथा टिक्काऊ विकास संबंधी स्टार्टअप शामिल हैं जहां दुनिया भर में कौशल की भारी कमी अनुभवी की जारी है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधियां विदेशों में रोजगार भारत में प्रशिक्षित अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक विवाद का कारण है। यहां अधिकारी विवादियों पार्टीयों अवैध अप्रवासन पर ध्यान देने के कारण है।

प्रवासन को बाधिय

